AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

डिजिटल इंडिया अभियान का ग्रामीण समाज पर प्रभावः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

ORIGINAL ARTICLE

Author
डॉ. आर्निका दीक्षित
विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग
गन्ना कृषक पी. जी. कॉलेज
पूरनपुर, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश, भारत

शोध सार

डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है इसका लक्ष्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करना है। इसके तहत इंटरनेट कनेक्टिविटी की पहुंच बढ़ाना कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देना नागरिकों को ऑनलाइन डॉक्युमेंट उपलब्ध कराना डिजिटल शिक्षा का विस्तार करना उपभोक्ताओं को डिजिटल बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना है। इस शोध पत्र का उद्देश्य डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का ग्रामीण समाज की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संरचना पर प्रभावों का समाजशास्त्रीय विशेषण करना है। इसके अध्ययन से स्पष्ट है कि आमजन को सरकारी सेवाओं की उपलब्धता वित्तीय समावेशन कृषि नवाचार महिला सशक्तिकरण तथा शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, परंतु डिजिटल विभाजन डिजिटल साक्षरता की कमी, साइबर सुरक्षा तथा इंटरनेट जैसी चुनौतियां भी आई है।

मुख्य शब्द

डिजिटल इंडिया, ग्रामीण समाज, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय समावेशन, सामाजिक परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण.

भूमिका

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग तकनीकी परिवर्तन नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन भी बदलाव करते हैं। भारत की 21वीं सदी संच7ार प्रौद्योगिकी की सदी मानी जाती है। भारत को इंटरनेट स्मार्टफोन और डिजिटल तकनीक ने लगभग प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। 19 वीं सदी में भारत में शिक्षा स्वास्थ्य बैंकिंग सेवा तथा सरकारी सेवाओं तक पहुंच सीमित थी। छोटे–छोटे सरकारी कार्यों के लिए ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते थे, परंतु डिजिटल इंडिया के माध्यम से महत्वपूर्ण बदलाव मिल रहे हैं। डिजिटल इंडिया के द्वारा सरकार ने इंटरनेट का विस्तार कॉमन सर्विस सेंटर, डिजिटल भुगतान प्रणाली, ऑनलाइन शिक्षा, सेवा, टेलीमेडिसिन तथा ई गवर्नेंस जैसे अनेक सुविधाएं नागरिकों को प्रदान की है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो डिजिटल तकनीक केवल सूचना प्राप्त करने की तकनीक नहीं बल्कि यह सामाजिक संबंधों सामाजिक संस्थाओं आर्थिक अवसरों तथा नागरिकों की जीवन शैली को भी प्रभावित करती है। इसके माध्यम से ग्रामीण युवाओं को रोजगार किसानों की कृषि पद्धतियों तथा नागरिकों की प्रशासन तक पहुंच में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। हालांकि इसके साथ डिजिटल विभाजन साइबर अपराध डिजिटल साक्षरता की कमी तथा तकनीकी असमानताओं की कमी जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। अतः इस विषय का समाजशास्त्रीय अध्ययन अत्यंत आवश्यक है।

अध्ययन की आवश्यकता

भारत गाँवों का देश है इसकी अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, यदि ग्रामीण समाज डिजिटल रूप से सशक्त नहीं होगा तो समग्र राष्ट्रीय विकास संभव नहीं है। यह अध्ययन निम्न कारणों से आवश्यक हैः

- ग्रामीण विकास में डिजिटल तकनीक के प्रभाव का मूल्यांकन।

- सामाजिक परिवर्तन की दिशा को समझना।
- नीति निर्माता द्वारा उपयोगी सुझाव प्रस्तुत करना।
- भविष्य के लिए डिजिटल नीतियों को तैयार करना।

अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध के निम्न उद्देश्य हैं:

- डिजिटल इंडिया अभियान की अवधारणा का अध्ययन करना।
- ग्रामीण समाज पर इसके सामाजिक प्रभाव का अध्ययन करना।
- डिजिटल बैंकिंग तथा वित्तीय समावेशन की भूमिका का विश्लेषण करना।
- महिलाओं के सशक्तिकरण में डिजिटल इंडिया की भूमिका का विशेषण करना।
- डिजिटल इंडिया अभियान की प्रमुख चुनौतियों का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना

डिजिटल इंडिया अभियान ने ग्रामीण समाज के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। डिजिटल इंडिया अभियान से ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों को सरकारी सेवाओं की उपलब्धता बढ़ी है। डिजिटल भुगतान प्रणाली ने वित्तीय समावेशन को मजबूती प्रदान की है। डिजिटल साक्षरता की कमी वर्तमान में ग्रामीण विकास में बाधा है।

शोध पद्धतियां

यह अध्ययन वर्णनात्मक तथा विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। इसमें मुख्य रूप से द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया जाएगा। इसमें भारत सरकार की रिपोर्टों, डिजिटल इंडिया से संबंधित आंकड़े, जनगणना रिपोर्ट, पुस्तकों तथा सरकारी वेबसाइटों का प्रयोग किया जाएगा।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का परिचय

इस कार्यक्रम का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलाव लाना है। इसके तीन प्रमुख उद्देश्य हैं:

- प्रत्येक नागरिक को डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना।
- सभी सरकारी सेवाओं को जनता के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराना।
- नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना।

डिजिटल इंडिया के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जैसे भारतनेट, कॉमन सर्विस सेंटर, डिजिटल भुगतान, डिजीलॉकर, ई–हॉस्पिटल, ई–नाम, उमंग, भीम, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान आदि जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

ग्रामीण समाज पर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का प्रभाव

(अ) **शिक्षा पर प्रभावः** डिजिटल इंडिया अभियान के पश्चात ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव जैसे ऑनलाइन शिक्षा का विस्तार स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना डिजिटल पुस्तकों तक विद्यार्थियों की पहुँच डिजिटल ज्ञान में परिवर्तन हुए हैं इसके प्रभाव से ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा पहुंची है। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी अब घर से ही ऑनलाइन माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, परंतु इसके साथ ही इंटरनेट की कमी, स्मार्टफोन का अभाव, डिजिटल साक्षरता की कमी इसकी प्रमुख समस्याएं भी हैं।

(ब) **डिजिटल बैंकिंग एवं वित्तीय समावेशनः** डिजिटल इंडिया अभियान के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार हुआ है। इसके माध्यम से जनधन खाता आधार आधारित बैकिंग यूपीआई का भुगतान, मोबाइल बैंकिंग का विकास हुआ है परिणामस्वरूप महिलाओं की वित्तीय भागीदारी पारदर्शिता में वृद्धि एवं बचत में वृद्धि हुई है।

(स) **महिला सशक्तिकरणः** इस अभियान के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं इसके कारण डिजिटल बैंकिंग सुविधा ऑनलाइन स्वरोजगार ई– कॉमर्स के माध्यम से उत्पादन की बिक्री बढ़ी है परिणामस्वरूप महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है, उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई और उन्हें सरकारी योजना का लाभ मिलने लगा है।

(द) **रोजगार एवं उद्यमिता:** डिजिटल तकनीक के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल मार्केटिंग ई–कॉमर्स ऑनलाइन शिक्षा जैसे क्षेत्रों में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं इसके प्रभाव से स्थानीय रोजगार के अवसरों में वृद्धि स्वरोजगार को बढ़ावा तथा पलायन में कमी आई है।

(य) **ई–गवर्नेंस एवं पारदर्शिता:** इसके माध्यम से ऑनलाइन जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, भूमि अभिलेख, छात्रवृत्ति आवेदन, राशन कार्ड, आय, निवास एवं जाति प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं जिससे भ्रष्टाचार में कमी समय की बचत एवं पारदर्शिता में वृद्धि हुई है।

डिजिटल इंडिया से संबंधित आंकड़े

इस योजना के द्वारा मोबाइल कनेक्टिविटी वाले गांव की संख्या 644131 गांव में से 629027 लगभग 97.65 प्रतिशत गांव को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ दिया गया है इनमें से 4जी कनेक्टिविटी वाले गांव की संख्या लगभग 96.8 प्रतिशत या 623512 है। भारत नेट के अंतर्गत 214325 ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड सेवा हेतु तैयार किया जा चुका है इसके माध्यम से 1301193 फाइबर टू द होम कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। देश भर में 5.18 लाख कॉमन सर्विस सेंटर कार्य कर रहे हैं जिनमें से 4.57 लाख ग्रामीण स्तर पर हैं। उमंग एप के द्वारा 2390 से अधिक सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं जिस पर 726. 43 करोड़ से अधिक लेन–देन दर्ज है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में 23834 करोड़ डिजिटल भुगतान का ब्यौरा उपलब्ध है। यूपीआई के माध्यम से मई 2026 में 23201.93 मिलियन लगभग (2320 करोड़) लेन–देन हुए इनका कुल मूल्य 29. 90 लाख करोड़ से अधिक है। इन आंकड़ों के अध्ययन से स्पष्ट है कि डिजिटल इंडिया ने ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट ब्रॉडबैंड डिजिटल साक्षरता ई–गवर्नेंस और डिजिटल भुगतान के विस्तार में उल्लेखनीय कार्य किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी पहुंच करोड़ों नागरिकों का डिजिटल प्रशिक्षण तथा भुगतान में वृद्धि इस अभियान की सफलता को दर्शाती है। उपरोक्त आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण भारत डिजिटल समावेशन की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है।

डिजिटल इंडिया अभियान की प्रमुख चुनौतियां

डिजिटल इंडिया अभियान से ग्रामीण समाज में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं फिर भी इसके सामने कई समस्याएं और चुनौतियां हैं:

- **आर्थिक असमानता:** ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश परिवार निर्धन होते हैं जो स्मार्टफोन कंप्यूटर एवं इंटरनेट का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं इससे डिजिटल सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाता।
- **भाषा की बाधा:** अनेक डिजिटल प्लेटफॉर्म केवल अंग्रेजी भाषा पर आधारित है। स्थानीय भाषाओं में पर्याप्त सामग्री और सेवाओं का अभाव है जो ग्रामीण उपयोगकर्ताओं के लिए कठिनाई उत्पन्न करती है।
- **ऑनलाइन धोखाधड़ी:** ऑनलाइन सेवाओं के बढ़ते उपयोग के कारण साइबर अपराध, फर्जी काल, डाटा चोरी आदि समस्याओं के कारण ग्रामीण नागरिक अधिक प्रभावित होते हैं।
- **डिजिटल साक्षरता की समस्या:** ग्रामीण क्षेत्र के निवासी कम शिक्षित होते हैं, उनके अंदर डिजिटल तकनीक के उपयोग का ज्ञान सीमित है इसके कारण उन्हें ऑनलाइन सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाता।
- **डिजिटल डिवाइड:** भारत के शहरों और महानगरों में हाई स्पीड इंटरनेट और स्मार्टफोन आसानी से उपलब्ध है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इंटरनेट बिजली और स्मार्ट फोन होने की समस्या बनी हुई है।

सुधार हेतु सुझाव

डिजिटल इंडिया अभियान को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव हैं:

- ग्रामीण क्षेत्र में उच्च गति इंटरनेट उपलब्ध कराया जाए।
- स्कूलों तथा पंचायत भवनों पर डिजिटल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएं।
- हिंदी, अंग्रेजी के अलावा स्थानीय भाषाओं में भी डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जाए।
- महिलाओं तथा किसानों और युवाओं के लिए विशेष डिजिटल कौशल कार्यक्रम संचालित करके उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए।
- डिजिटल भुगतान को विश्वसनीय और सरल बनाया जाए।
- कॉमन सर्विस सेंटरों की संख्या में वृद्धि की जाए।

- ग्रामीण क्षेत्र की बिजली आपूर्ति में सुधार किया जाए।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का विस्तार करके अधिक से अधिक लोग जोड़े जाएं।
- साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल जागरूकता पर नियमित सेमिनारों सभाओं का आयोजन करके प्रचार प्रसार जाए।

निष्कर्ष

डिजिटल इंडिया सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके द्वारा शिक्षा स्वास्थ्य कृषि बैंकिंग ई–गवर्नेंस महिला सशक्तिकरण तथा रोजगार के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार हुए हैं। इसके माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को सरकारी सेवाओं वित्तीय सुविधाओं को सरल पारदर्शी बनाया जा रहा है।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह अभियान तकनीकी परिवर्तन नहीं बल्कि सामाजिक संरचना सामाजिक संबंधों और विकास की प्रक्रिया में परिवर्तन है। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरुकता सहभागिता और आत्मनिर्भरता बढ़ी है। हालांकि डिजिटल विभाजन डिजिटल साक्षरता की कमी साइबर सुरक्षा संबंधी समस्याएं और चुनौतियां आज भी मौजूद हैं इन समस्याओं का समाधान प्रभावी नीतियों और व्यापक जन जागरूकता के माध्यम से किया जा सकता है। यदि उपरोक्त सभी चुनौतियों का समाधान किया जाए तो डिजिटल इंडिया अभियान ग्रामीण भारत को समावेशी सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान प्रदान करेगा जो विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण होगा।

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल, ए.एन. (2022) *भारतीय अर्थव्यवस्था.* न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
2. सिंह, योगेन्द्र (2018) *भारत में सामाजिक परिवर्तन.* रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
3. श्रीनिवास, एम. एन. (अनूदित संस्करण 2019) *आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन.* राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
4. दुबे, श्यामाचरण (2016) *भारतीय समाज.* राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली।
5. पाण्डेय, राम शंकर (2024) *ग्रामीण विकास.* अखण्ड पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
6. भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिजिटल इंडिया कार्यक्रम– वार्षिक प्रतिवेदन 2025।
7. भारत सरकार. (2015) *डिजिटल इंडिया कार्यक्रम दस्तावेज.* इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. नीति आयोग (2025) *न्यू इंडिया @75: रणनीति दस्तावेज.* भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. भारत सरकार (2025) ग्रामीण विकास मंत्रालय. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, नई दिल्ली।
10. भारत सरकार, राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस प्रभाग ई–गवर्नेंस एवं डिजिटल सेवाएँ– वार्षिक रिपोर्ट– 2024, 2025, नई दिल्ली।
11. भारतीय रिजर्व बैंक, वार्षिक प्रतिवेदन (2025) नई दिल्ली।
12. कॉमन सर्विस सेंटर ई–गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड. वार्षिक प्रतिवेदन– 2025, नई दिल्ली।
13. भारत सरकार (2011) *भारत की जनगणना 2011.* भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, नई दिल्ली।
14. संयुक्त राष्ट्र. ई–गवर्नेंस सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025, नई दिल्ली।

––==00==––